have been lying vacant in the office of District and Session Judge, Delhi since long;

(b) whether it is also a fact that selection formalities of the eligible candidates *who* were sponsored by the Employment Exchanges have since been completed; and

(c) if so, by when offer of appointment will be issued to the selected candidates?

'THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) 85 posts each of Ahlmads, Assistant Ahlmads and Copyists were tanctioned by the Government in September, 1990. These 255 posts were notified by the office of the District and Sessions Judge. Delhi to the Employment Exchange for sponsoring names. Thereafter a written lest was held for the candidates sponsored by the Employment Exchange and, a typing test was later held on 26.4.92 for those who passed the written test. Offer of appointment will be issued to the selected candidates as soon as the results are finalised and other formalities are completed.

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में विफलता

1835. **श्री अजीत जोगी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद भी देश में समान रूप से क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ; और

(घ) चालू और अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या प्रयास किए जायेंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) संतुलित क्षेत्रीय विकास निसंदेह योजना प्रक्रिया का एक भाग है । बहरहाल, जहां तक क्षेत्रीय विकास का संबंध है, कुछ अंतर्निहित तत्वों और ऐतिहासिक और संसाधन प्रचुरता में भिन्नताओं, आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धताओं में विषमताओं, भू-आकृति-विज्ञान संबंधी तत्वों और भौगोलिक परिस्थितियों जैसी क्षेत्रों की विशेषताओं से इस उद्देश्य के कार्यान्वयन में शिथिलता आती है ।

किसी क्षेत्र विशेष के विकास की जिम्मेदारी मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार की है। इसमें केन्द्र सरकार संशोधित फार्मूला जो पहले "गाडगिल फार्मूला" के नाम से जाना जाता था, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत संसाधनों के अन्तरण की कार्यविधि और वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों के अन्तरण द्वारा राज्यों की मदद की जाती है।

जनजातीय क्षेत्र देश के पिछड़े क्षेत्रों का एक भाग है । ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय उप-योजना तैयार की गई है। जनजातीय उपयोजना के तहत परिवार मूलक और आधारभूत संरचना विकास संबंधी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं । संस्थागत ऋण, आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं, विपणन, कच्चे माल की आपूर्ति, सिचाई सुविधाएं और शिक्षा तथा प्रशिक्षण जैसे इनपुट उपलब्ध कराते हुए जनजातीय परिवारों की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया है ।

जनजातीय उप-योजना बीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और इसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले सभी अनुसूचित क्षेत्र और तहसील और ब्लाक शामिल हैं । इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी जनजातीय जनसंख्या वाले स्थान भी जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं । जनजातीय उपयोजनाएं एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी), जनजातीय केंद्रीकरण

स्थानों (एमएडीए पाकेट) और समुदायों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस समय, 193 आईटीडीपी, 249 एमएडीए पाकेट, जनजातीय केंद्रीकरण के 17 समूह और 74 आदिम जनजातीय समूह परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। जनजातीय उपयोजना की नीति आठवीं योजना के दौरान जारी रहेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक और ठोस लाभ लक्ष्य तक पहुंचे, इसे आयोजना का एक प्रभावी उपकरण बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी।

Welfare Scheme in Rural Areas for the Urban Poor

1836. fHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleasad to state;

(a) whether 't is a fact that a large number of Ministries have their separate eprogrammes for funding of voluntary agencies engaged in implementation of welfare schemes in rural areas and for the arban poor; and

(b) if so, the details of the amount spent by each Ministry during the last three years through voluntary agencies and the criteria laid down therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Details are being collected and will be laid on the Table of the House.

Areas covered by Integrated Rural Energy Planning

1837. SHRIMATI KAMLA SINHA; Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the deatils of areas which are covered by the Integrated Rural Energy Planning and what further extension of this programme are intended by Government in the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENER_ GY SOURCES (SHRI SUKH RAM): Tho Integrated Rural Energy Plannng Programme is being taken up in selected blocks in all States and UTs except Chandigarh. Up to 1991-92, 252 blocks have been covered under this programme. The) Statewise break up of the blocks covered under the programme is given in the attached statement. (See below) The Programme involved setting up of project cells in the selected blocks which would prepare and monitor the implementation of the block level IREP Projects. It is proposed to extend the programme at the; rate of about 100 blocks a year in the 8th Plan. The details of the programme in the 8th Plan are being worked out.

Statement

Statewise break up of the Blocks covered under IREP Programme

Name of State|UTs	No. of IREP Blocks
Andhra Pradesh	8 (Mandals)
Arunachal Pradesh	4
Assam	10
Bihar	7
Goa	4
Gujarat	15
Haryana	*14*
Himachal Pradesh	17
Jammu & Kashmir	5
Karnataka	9
Kerala	8
Madhya Pradesh	21
Maharashtra	13
Manipur	4
Meghalaya	6
Mizoram	3
Nagaland	2
Orissa	5
Punjab	8
Rajasthan	7
Sikkim	3
Tamil Nadu	11
Tripura	5
Uttar Pradesh	48
West Bengal	7
(i) TOTAL State;	239